

एनसीएलटी ने दर्ज किया अब तक का सर्वश्रेष्ठ तिमाही प्रदर्शन; चंडीगढ़ बेंच ने 1,079 करोड़ रुपये की 9 समाधान योजनाओं को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 8 अक्टूबर, 2026: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के दौरान 107 समाधान योजनाओं को मंजूरी देकर अपना अब तक का उच्चतम त्रैमासिक प्रदर्शन दर्ज किया है, जिसमें चंडीगढ़ बेंच ने 1,079.07 करोड़ रुपये की योजनाओं से जुड़ी 9 मंजूरियों का योगदान दिया है।

जुलाई और सितंबर 2026 के बीच स्वीकृत 107 समाधान योजनाएं अपनी स्थापना के बाद से किसी भी तिमाही में अधिकरण द्वारा स्वीकृत की गई सबसे अधिक संख्या हैं। यह आंकड़ा एनसीएलटी के इतिहास में दूसरी तिमाही के दौरान दर्ज की गई मंजूरियों की सबसे अधिक संख्या भी है।

चंडीगढ़ बेंच इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ताओं में से एक बनकर उभरी, जिसने तिमाही के दौरान नौ समाधान योजनाओं को मंजूरी दी। चंडीगढ़ बेंच द्वारा अनुमोदित योजनाओं का संचयी मूल्य 10,79,06,84,000 रुपये या लगभग 1,079.07 करोड़ रुपये था।

एनसीएलटी की सभी बेंचों में, तिमाही के दौरान स्वीकृत 107 समाधान योजनाएं 11,000 करोड़ रुपये से अधिक के कुल स्वीकृत योजना मूल्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। मुंबई बेंच ने सबसे अधिक 35 योजनाओं को मंजूरी दी, इसके बाद प्रिंसिपल बेंच और नई दिल्ली बेंच ने 29 योजनाओं को मंजूरी दी, जबकि चंडीगढ़ उल्लेखनीय मंजूरियों वाली बेंचों में शामिल रहा।

यह नवीनतम प्रदर्शन पिछले वर्षों की समान तिमाहियों की तुलना में पर्याप्त सुधार दर्शाता है। एनसीएलटी ने वित्त वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 60, वित्त वर्ष 2024-25 में 57, वित्त वर्ष 2023-24 में 82, वित्त वर्ष 2022-23 में 47 और वित्त वर्ष 2021-22 में 20 समाधान योजनाओं को मंजूरी दी थी। इसलिए चालू तिमाही का 107 का आंकड़ा अधिकरण द्वारा दर्ज किया गया अब तक का सर्वोच्च त्रैमासिक प्रदर्शन है।

वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में 185 समाधान योजनाओं को मंजूरी

दूसरी तिमाही के दौरान 107 मंजूरियों ने, पहली तिमाही में 78 मंजूरियों के बाद, वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के दौरान स्वीकृत एनसीएलटी की कुल समाधान योजनाओं की संख्या को 185 तक पहुंचा दिया है।

इसके परिणामस्वरूप एनसीएलटी की विभिन्न बेंचों में स्वीकृत समाधान योजनाओं की संचयी संख्या 30 सितंबर, 2026 तक 1,735 तक पहुंच गई है। इन योजनाओं के तहत कुल स्वीकृत राशि लगभग 4.89 लाख करोड़ रुपये है।

अधिकरण का यह प्रदर्शन समाधान योजनाओं की मंजूरी चाहने वाले आवेदनों के निरंतर प्रवाह के बीच आया है। 30 सितंबर तक, 294 समाधान योजनाएं मंजूरी के विचारार्थ लंबित थीं, जबकि अन्य 41 मामलों में आदेश सुरक्षित रख लिए गए थे। इस प्रकार, 335 मामले इन दो चरणों में थे, जो अप्रैल 2026 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नोट किए गए मंजूरी की प्रतीक्षा कर रहे 363 आवेदनों की तुलना में कमी को दर्शाता है।

लंबित मामलों और केस प्रबंधन पर ध्यान

एनसीएलटी ने केस-फ्लो प्रबंधन में सुधार करने, रजिस्ट्री प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और उपलब्ध न्यायिक संसाधनों का अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए प्रशासनिक और संस्थागत उपायों की एक श्रृंखला शुरू की है।

अपनी 16 बेंचों में लंबित मामलों और निपटान संबंधी आंकड़ों को एकत्र करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक मजबूत तंत्र पेश किया गया है। यह प्रणाली बेंचों और न्यायालयों में कार्यभार की अधिक व्यापक तस्वीर प्रदान करती है और मामलों के पुनर्वितरण और न्यायिक संसाधनों के उपयोग के संबंध में बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाती है।

अधिकरण ने मामलों के पंजीकरण और लिस्टिंग के लिए एक संरचित रूपरेखा भी शुरू की है, जिसका उद्देश्य रजिस्ट्री प्रथाओं में अधिक एकरूपता लाना और कॉज लिस्ट की व्यवस्थित तैयारी सुनिश्चित करना है। यह ढांचा पुराने लंबित मामलों को उचित प्राथमिकता प्रदान करता है, जिसमें आईबीसी (IBC) प्रवेश मामले और समाधान योजनाओं के अनुमोदन से संबंधित आवेदन शामिल हैं।

जहां भी आवश्यक हो, विशेष बेंचों का भी गठन किया गया है, साथ ही कार्यभार के पुनर्वितरण और उपलब्ध अदालती समय को अधिकतम करने के उपाय भी किए गए हैं।

प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय तक पहुंच

अपने निरंतर डिजिटल परिवर्तन के हिस्से के रूप में, एनसीएलटी ने ई-निरीक्षण और ई-प्रमाणित प्रति (e-Certified Copy) सेवाएं शुरू की हैं, जिससे अधिवक्ताओं, वादियों और अन्य हितधारकों को न्यायिक रिकॉर्ड और प्रमाणित प्रतियों तक अधिक आसानी से और तेजी से पहुंचने में मदद मिलती है।

ये पहल अधिकरण के व्यापक डिजिटल परिवर्तन का हिस्सा हैं, जिसमें नया रूप दिया गया एनसीएलटी पोर्टल और ई-कोर्ट्स 2.0 का निरंतर क्रियान्वयन शामिल है।

संस्थागत बाधाओं के बावजूद प्रदर्शन

यह नवीनतम प्रदर्शन संस्थागत क्षमता और बुनियादी ढांचे से संबंधित बाधाओं के बावजूद सामने आया है। अध्यक्ष के अतिरिक्त 62 सदस्यों की स्वीकृत क्षमता के मुकाबले, अधिकरण में वर्तमान में 48 सदस्य हैं, जिससे 14 पद रिक्त हैं। वर्तमान में, 13 अदालतें पूरे दिन के आधार पर काम कर रही हैं जबकि 18 अदालतें आधे दिन के आधार पर काम कर रही हैं। वर्तमान कैलेंडर वर्ष के अंत तक चार अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल भी समाप्त होने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की नियुक्ति और बुनियादी ढांचे की कमियों से संबंधित मुद्दों का स्वतः संज्ञान भी लिया है।

इन चुनौतियों के बावजूद, अधिकरण ने केस प्रबंधन में सुधार करने, परिहार्य देरी को कम करने और अपने पास उपलब्ध न्यायिक और प्रशासनिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग करने पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में चंडीगढ़ बेंच द्वारा 1,079 करोड़ रुपये से अधिक की नौ समाधान योजनाओं को मंजूरी दिए जाने के साथ, चंडीगढ़ ने एनसीएलटी के रिकॉर्ड राष्ट्रीय प्रदर्शन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अधिकरण निरंतर संस्थागत सुधार, मामलों के समय पर निपटान, कुशल केस प्रबंधन और उपलब्ध संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है।
